दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जून (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 3
- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किस्मों का दूसरे राज्यों को भी मिलेगा लाभ 3
- रोहतक पीजीआई बनेगा हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 4
- पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 का शुभारंभ 5
- हरियाणा को मिली 2,366 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात 5
- जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में दाँव लगाएंगी मंजू संधू 5
- संत कबीर कुटीर' के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास 6
- खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने 52 गोल्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया 6
- मुख्यमंत्री ने की हरियाणा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा 7
- हरियाणा साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देगा 7
- 20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतूओं को मालिकाना हक देगी हरियाणा सरकार 8
- हरियाणा ने इज़राइल के साथ जल सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये 8
- हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर 'ई-श्रद्धांजलि' प्लेटफॉर्म का शुभारंभ 9
- कुओर्ताने गेम्स में जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक 9
- अरावली सुरंग 9
- भीम पुरस्कार 10
- नशामुक्त अभियान की कार्ययोजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा 10
- हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन 11
- हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 को मंज़ूरी 11
- हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 को मंज़ूरी 12
- हरियाणा में पैक्स का होगा डिजिटलीकरण 12
- हरियाणा में गाँवों की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू 13

नोट :

हरियाणा

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2022 को हरियाणा सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- ईजीओएस का कार्यक्षेत्र राज्य मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना तथा पायलट आधार पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण में सभी उपयोगी सेवाओं के साथ सड़कों, रेललाइन आदि के निर्माण हेतु विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के लिये एक प्रक्रिया और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना है।
- इसके अतिरिक्त हरियाणा में 'राज्य रसद समन्वय प्रकोष्ठ' अब 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (एनएमपी) के लिये 'तकनीकी सहायता इकाई' (टीएसयू) के रूप में कार्य करेगा। यह प्रकोष्ठ प्रदेश में 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (एनएमपी) के संचालन के लिये राज्यस्तरीय संस्थागत सेटअप के रूप में काम करेगा।
- गौरतलब है कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या 'नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान' लॉन्च किया है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - ज़मीनी स्तर पर कार्य में तेज़ी लाने, लागत को कम करने और रोज़गार सृजन पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  - गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को शामिल करना।
  - लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना।
  - 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे (एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में) बनाना।
- इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा, साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
- यह वर्ष 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किस्मों का दूसरे राज्यों को भी मिलेगा लाभ

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2022 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा विकसित गेहूँ, सरसों व जई की उन्नत किस्मों का लाभ अन्य राज्यों को भी प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तकनीकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देते हुए गुरुग्राम की निजी क्षेत्र की प्रमुख बीज कंपनी मैसर्स देव एग्रीटेक प्रा.लि. से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विश्वविद्यालय द्वारा गेहूँ की डब्ल्यूएच 1270, सरसों की आरएच 725 व जई की ओएस 405 किस्मों को विकसित किया गया है।
- फसलों की उपरोक्त उन्नत किस्मों के लिये विश्वविद्यालय की ओर से गुरुग्राम की मैसर्स देव एग्रीटेक प्रा.लि. को तीन वर्ष के लिये गैर-एकाधिकार लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके तहत यह बीज कंपनी गेहूँ, सरसों व जई की उपरोक्त किस्मों का बीज उत्पादन व विपणन कर सकेगी।
- सरसों की आरएच 725 किस्म की फलियाँ अन्य किस्मों की तुलना में लंबी व उनमें दानों की संख्या भी अधिक होती है और तेल की मात्रा भी ज़्यादा होती है।
- गेहूँ की डब्ल्यूएच 1270 किस्म को गत वर्ष देश के उत्तर-दक्षिण ज़ोन में खेती के लिये अनुमोदित किया गया है। इस किस्म की औसत पैदावार 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि उत्पादन क्षमता 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12 प्रतिशत है।
- जई की ओएस 405 किस्म देश के सेंट्रल ज़ोन के लिये उपयुक्त किस्म है। इसकी हरे चारे की पैदावार 51.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि दानों का उत्पादन 16.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

रोहतक पीजीआई बनेगा हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2022 को हरियाणा राज्य के पीजीआईएमएस के निदेशक डॉ. एस.एस. लोहचब ने रोहतक ज़िले के पीजीआई को हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- पीजीआई के हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से दिल की हर तरह की बीमारी के इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी।
- इसी संदर्भ में हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिल के मरीजों को हर तरह का इलाज मुहैया कराने के लिये उपकरण, चिकित्सक, स्टाफ व अन्य ज़रूरी चीजों का खाका तैयार किया जा रहा है।
- वर्तमान में राज्य के हृदय रोगियों को इलाज के लिये चंडीगढ़, जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है।
- साथ ही सरकार द्वारा दूसरे गंभीर रोगों के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को दूसरे रोगों का भी बेहतर इलाज मुहैया हो सके।
- सरकार का प्रयास इस संस्थान को हृदय रोग की सुपर स्पेशियलिटी के रूप में विकसित करने का है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के अंत्योदय मेलों का आयोजन 10 जून से किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोज़गार और रोज़गार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय शुरू में 1.00 लाख रुपए और बाद में 1.80 लाख रुपए तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।
- इसमें राज्य के उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वर्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है।
- इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वर्ष 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया गया था।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50 हज़ार परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

नोट :

पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

4 जून, 2022 को हरियाणा के पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021' के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 का आयोजन 13 जून तक 5 शहरों (पंचकूला, शाहाबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली) में आयोजित किया जाएगा, जबकि ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकूला इन खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य आयोजन स्थल है।
- इस आयोजन में भारत के 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 2,262 लड़कियों सहित 4,700 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में कुल 25 खेल होंगे, जिनमें भारत के 5 स्वदेशी खेल- कलारीपयट्टू, थांग-ता, गतका, मल्लखंब और योगासन शामिल हैं।
- इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली बार पाँच पारंपरिक खेलों, जैसे- गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मलखंब और योगासन को भी शामिल किया गया है।
- गौरतलब है कि खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार हरियाणा ने राज्यव्यापी मशाल रिले का भी आयोजन किया। विशेषरूप से डिजाइन किये गए कैंटर ने सभी ज़िलों का दौरा किया और खेलों को बढ़ावा दिया तथा बच्चों को खेल के लिये प्रोत्साहित किया।

हरियाणा को मिली 2,366 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात

चर्चा में क्यों ?

4 जून, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को 2366 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग 997 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में बनने वाले गुरु तेगबहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा लगभग 945 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज, कैथल का शिलान्यास किया।
- इसके अलावा, उन्होंने ज़िला फतेहाबाद में 2800 मेगावाट गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना (परमाणु ऊर्जा परियोजना) के लिये जलापूर्ति चैनल प्रणाली के निर्माण की भी आधारशिला रखी। इस परियोजना पर लगभग 394 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2800 मेगावाट गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना (परमाणु ऊर्जा परियोजना) केंद्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है। यह हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा।
- यह संयंत्र 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिसमें से हरियाणा को 1400 मेगावाट बिजली की सप्लाई होगी।
- इस संयंत्र के चालू होने से इस क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों को भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। इस संयंत्र के आसपास के इलाकों को न केवल रोज़गार उपलब्ध होगा, बल्कि आर्थिक समृद्धि भी आएगी।

जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में दाँव लगाएंगी मंजू संधू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के हिसार ज़िले के कौथकलाँ की 18 वर्षीय पहलवान मंजू संधू का चयन इटली में होने वाली जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग के लिये हुआ है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 22 जून से 30 जून, 2022 तक इटली में होने वाली जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में मंजू संधू 72 किग्रा. भारवर्ग में खेलेंगी।
- गौरतलब है कि राँची में 26 मई से 29 मई तक जूनियर रैंकिंग नेशनल में मंजू ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा लखनऊ में 2 जून को जूनियर एशिया चैंपियनशिप के लिये हुए ट्रायल में प्रथम स्थान पर आई थीं। इन दोनों के बेस पर मंजू का जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग के लिये चयन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मंजू संधू ने 2018-19 में पूना में हुए खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक तथा 2019-20 में गुवाहाटी में हुए खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता था।
- मंजू पिछले पाँच साल से उमरा के एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में कुश्ती कोच संजय मलिक से प्रशिक्षण ले रही हैं।

संत कबीर कुटीर' के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में राज्यस्तरीय संत कबीर दास जयंती समारोह में घोषणा की कि चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को अब 'संत कबीर कुटीर' के नाम से जाना जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और धर्मशालाओं में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने के अलावा केंद्र की तर्ज़ पर सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के दौरान कैडरवार आरक्षण के प्रावधान की भी घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति (एससी) के साथ ही पिछड़े वर्ग (बीसी) की धर्मशालाओं में भी पुस्तकालय की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, सभी समुदायों की धर्मशालाओं में पाँच किलोवाट के सौर संयंत्र स्थापित करने के लिये 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- खट्टर ने कहा कि एनआईटी और आईआईटी में आरक्षण की व्यवस्था के लिये केंद्र के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि 51 लाख रुपए तक की कोई भी परियोजना समाज की साढ़े पाँच एकड़ भूमि पर सरकार द्वारा बनाई जाएगी, यदि कोई शैक्षणिक संस्थान इसकी मांग करता है।
- उन्होंने राज्य के लोगों के लिये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत कबीर और गुरु रविदास की जन्मस्थली की नि:शुल्क तीर्थयात्रा की घोषणा की। साथ ही राज्य में एक स्वास्थ्य संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम संत कबीर के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 'संत-महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत राज्यस्तर पर संतों और महान हस्तियों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- राज्य सरकार ने गुरु तेग बहादुर की जयंती, गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर भी राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया है। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 'पराक्रम दिवस', संत कबीर दास जी की जयंती भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं।

खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने 52 गोल्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2022 को हरियाणा के पंचकूला में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा ने 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 कांस्य पदक लेकर कुल 137 पदक हासिल करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 कांस्य पदक सहित कुल 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे नंबर पर रहे कर्नाटक ने 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 कांस्य पदक हासिल करके कुल 67 पदक प्राप्त किये।

नोट :

- हरियाणा ने कुश्ती में सबसे ज़्यादा 38 पदक जीते, जिनमें 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 कांस्य शामिल हैं।
- बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन बना। बॉक्सिंग में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते।
- हरियाणा को एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 कांस्य मिले । इसी प्रकार जूडो में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांस्य पदक तथा साइक्लिंग में 2 गोल्ड और 6 कांस्य पदक हासिल किये।
- हरियाणा के खिलाड़ियों ने स्विमिंग में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक, शूटिंग में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य तथा योगासन में 1 गोल्ड और 5 कांस्य, थांग ता में 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक तथा गतका में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर जीते।
- इसके अलावा हरियाणा के खिलाड़ियों ने हैंडबॉल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, हॉकी में 1 गोल्ड, आर्चरी में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, बैडमिंटन में 1 गोल्ड और 1 कांस्य, फुटबॉल में 1 कांस्य, जिम्नास्टिक्स में 1 कांस्य, कबड्डी में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, टेबल टेनिस में 1 सिल्वर, टेनिस में 1 कांस्य और वॉलीबॉल में 2 सिल्वर मेडल हासिल किये।
- गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 जून से 13 जून, 2022 तक पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम समेत चंडीगढ़, दिल्ली, शाहाबाद और अंबाला में आयोजित किये गए थे।

मुख्यमंत्री ने की हरियाणा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के चौथे संस्करण के समापन समारोह में देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिये हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलकूद की अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मद्देनज़र पंचकूला में 200 खिलाड़ियों के ठहरने की सुविधा वाला एक छात्रावास खोला जाएगा। इसके ज़रिये खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ मुहैया कराने के साथ ही उन्हें खेल में दक्ष बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये दी जा रही पुरस्कार राशि को दोगुना करने की भी घोषणा की।
- स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 60,000 रुपए और कांस्य पदक विजेता को 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिये क्रमशः 50,000 रुपए, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए निर्धारित की गई थी।
- इसके अलावा उन्होंने खेलों में भाग लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 5000 रुपए देने की भी घोषणा की।
- खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने ज़मीनी स्तर पर खेल का बुनियादी ढाँचा तैयार किया है। राज्य में वर्ष भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये खेल कैलेंडर भी तैयार किया गया है।
- बच्चों में खेल संस्कृति विकसित करने के लिये राज्य में 1100 खेल नर्सरी खोली जा रही हैं। इससे राज्य के करीब 25,000 नवोदित खिलाड़ियों को फायदा होगा।

हरियाणा साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देगा

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात चंडीगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग और एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित स्कूली छात्रों के एक पर्वतारोहण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही।
- उन्होंने कहा कि राज्य में नियमित खेलों की तर्ज पर एडवेंचर को आगे ले जाने के लिये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, उसे मुहैया कराया जाएगा, ताकि हर युवा एडवेंचर में हिस्सा ले सके।
- हरियाणा में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये मोरनी में सरदार मिल्खा सिंह क्लब की स्थापना की गई है, जिससे इस क्षेत्र में कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा युवाओं के लिये अरावली पहाड़ियों में ट्रैकिंग रूट भी तलाशे जा रहे हैं, ताकि दक्षिण हरियाणा में भी एडवेंचर स्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। साहसिक प्रशिक्षण देकर 1000 युवाओं को काबिल बनाया जाएगा।

20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतूओं को मालिकाना हक देगी हरियाणा सरकार

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 20 साल से ज़मीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर में लगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों की समस्याएँ सुनने के बाद यह घोषणाएँ की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2000 तक जिस ज़मीन पर घुमंतू जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो सरकार वह ज़मीन उनके नाम करेगी।
- इसके लिये शर्त यह है कि ज़मीन 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिये कुछ भुगतान लिया जाएगा। इसके अलावा, परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से चिह्नित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपए वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे।

हरियाणा ने इज़राइल के साथ जल सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में हरियाणा सरकार और इज़राइल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जानकारी देते हुए अटल भूजल योजना हरियाणा के सह परियोजना निदेशक एवं इंजीनियर-इन-चीफ डॉ. सतबीर सिंह कादयान ने बताया कि संयुक्त सहयोग समझौते पर विदेश मंत्रालय, इज़राइल के राजदूत इनायत शेलिन (Head MASHAV) के साथ हस्ताक्षर किये गए हैं।
- डॉ. सतबीर सिंह कादयान ने बताया कि जल क्षेत्र को बदलने और एसडीजी, 2030 लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इज़राइल हरियाणा के साथ साझेदारी कर रहा है।
- इस संयुक्त घोषणा के हिस्से के रूप में, MASHAV जल प्रबंधन क्षेत्र में हरियाणा के विकास के लिये ज्ञान, क्षमता निर्माण और इज़राइली प्रौद्योगिकियों को साझा करेगा।
- गौरतलब है कि माशव (MASHAV) इज़रायल के विदेश मामलों के मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी के लिये हिब्रू का संक्षिप्त नाम है। माशव विकासशील देशों में इज़रायल के विश्वव्यापी विकास और सहयोग कार्यक्रमों के डिजाइन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

नोट :

हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर 'ई-श्रद्धांजलि' प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2022 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर 'ई-श्रद्धांजलि' प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू की गई इस सुविधा में भारत के वीर (पुलिस शहीदों की सूची), यूजर्स मैसेज, जो पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना है, आदि जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।
- इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए डीजीपी ने कहा कि 'ई-श्रद्धांजलि' सुविधा सभी को आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने में बहादुर व जांबाज शहीद पुलिस जवानों के योगदान को याद करने के लिये एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगी।
- अब सभी अधिकारी व जवानों सहित अन्य नागरिकों को 1 नवंबर, 1966 से हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कर्त्तव्य परायणता के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हरियाणा के तमाम वीर व जांबाज पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
- नागरिक हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanapolice.gov.in पर जाकर होमपेज पर प्रदर्शित 'ई-श्रद्धांजलि' विकल्प का चयन कर पुलिस के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्त्ता शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये संदेश भी लिख सकते हैं, जिसे आगे वेबपेज पर प्रदर्शित किया जाएगा।

कुओर्ताने गेम्स में जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

18 जून, 2022 को फिनलैंड में आयोजित कुओर्ताने गेम्स में हरियाणा के पानीपत ज़िले के जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- नीरज चोपड़ा इस गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 86.69 मीटर तक जेवेलियन पेंककर यह उपलब्ध हासिल की है।
- उन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के केशरन वाल्काट और ग्रेनाडा के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।
- विदित है कि जून महीने में ही नीरज चोपड़ा ने पावे नूरमी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता है।

अरावली सुरंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक वाई.पी. शर्मा ने बताया कि दिसंबर, 2022 तक अरावली सुरंग में ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अरावली सुरंग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत निर्मित विश्व की पहली ऐसी सुरंग है, जिससे होकर एक साथ दो ट्रेनों को निकाला जा सकता है।

नोट :

- हरियाणा के नूँह ज़िले में निर्मित यह सुरंग कॉरिडोर के दादरी-रेवाड़ी प्रखंड का हिस्सा है।
- 800 करोड़ रुपए से निर्मित इस सुरंग का निर्माण कार्य नवंबर, 2019 में प्रारंभ हुआ तथा जुलाई, 2021 में पूरा किया गया है।
- इस सुरंग में ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ डबल डेकर ट्रेनों के संचालन की भी सुविधा उपलब्ध है।

भीम पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2022 को पंचकूला में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार समारोह में हरियाणा के 52 खिलाड़ियों को राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार 'भीम पुरस्कार' प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कार पिछले चार वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में उपलब्धियों के लिये दिये गए हैं।
- 52 भीम अवार्ड विजेताओ में टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया, टोक्यो पैरालिंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया, रजत और कांस्य पदक विजेता सिंहराज अधाना तथा टोक्यो पैरालिंपिक के ही कांस्य पदक विजेता आर्चर हरविंदर सिंह शामिल हैं।
- पुरस्कार विजेताओं को भीम की एक लघु प्रतिमा और प्रशस्ति-पत्र के साथ 5 लाख रुपए नकद दिये गए।
- इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं को हरियाणा सरकार द्वारा 5,000 रुपए का मासिक मानदेय भी दिया जाएगा।

नशामुक्त अभियान की कार्ययोजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2022 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य को नशामुक्त करने के लिये करनाल की मधुबन पुलिस अकादमी स्थित हर्षवर्धन ऑडीटोरियम में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नशामुक्त अभियान की कार्ययोजना को सार्वजनिक कर एक पुस्तिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे में लिप्त हो रहे युवाओं के स्वास्थ्यवर्धन और उनके पुनर्वास के लिये ब्यूरो की यह पहल अनूठी साबित होगी। इस प्लान में नशे से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान करके उसे उचित परामर्श और चिकित्सा देकर उसका पुनर्वास किया जाना शामिल है।
- प्लान में 'प्रयास' और 'साथी' नाम से दो ऐप विकसित किये गए हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। साथ ही इसमें ट्रेनिंग का विषय भी जोड़ा गया है।
- उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें रचनात्मक कार्यों, विशेषकर खेलों से जोड़ने के लिये प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियाँ बनाई जा रही हैं, इनसे युवाओं में खेलों का रुझान बढ़ेगा और उनमें खेल भावना का सृजन होगा।
- प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिये उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धाकड़ का अर्थ है- हिम्मत वाला व्यक्ति। इस कार्यक्रम के तहत क्लास के पाँच बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो सुस्त, एकाकी रहने वाले व चोरी-छिपे नशा करने वाले बच्चे की पहचान करेंगे और उसकी सूचना क्लास टीचर, यानी सीनियर धाकड़ को देंगे। सीनियर धाकड़ सूचना प्राप्त करने के बाद संबंधित प्रिंसिपल/हैड मास्टर को रिपोर्ट करेंगे, जो नोडल धाकड़ कहलाएगा।
- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और सुपरविज़न के लिये राज्य, ज़िला, उपमंडल, क्लस्टर और गाँव/वार्ड स्तर पर मिशन टीमें नशे से ग्रस्त व्यक्ति की काउंसिलिंग, उपचार व पुनर्वास के लिये काम करेंगी।

नोट :

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस संशोधन के अंतर्गत अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी।
- यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) प्रथम संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे।
- इस संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिये अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) के लिये चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी।

हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग व व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना और हरियाणा में 115-120 नए डाटा सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है।
- इन डाटा सेंटरों के स्थापित होने से 7500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
- हरियाणा में स्थापित 1 मेगावाट और उससे अधिक बिज़ली की खपत करने वाला कोई भी डाटा सेंटर इस नई नीति के तहत लाभ उठाने के लिये पात्र होगा।
- इस नीति के तहत राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क में छूट के साथ अन्य आर्थिक लाभ प्रदान किये जाएंगे जैसे रोजगार सृजन सब्सिडी।
  - हरियाणा सरकार डाटा सेंटर से संबंधित बुनियादी ढाँचे को हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत एक अलग इकाई के रूप में शामिल करेगी, जो एफएआर में छूट और बिल्डिंग डिजाइन तथा निर्माण मानदंड प्रदान करेगी।
- हरियाणा सरकार डाटा सेंटर्स को एक अलग अवसंरचना उद्योग तथा ऊर्जा सघन उद्योग के रूप में घोषित करेगी।
- हरियाणा सरकार डाटा केंद्रों को हरियाणा आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम, 1974 के तहत एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करेगी।
- राज्य संचार और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से डाटा सेंटरों के लिये स्वीकृति के आवेदनों को 'राइट ऑफ वे' मुहैया करवाया जाएगा।

नोट :

हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार की गई एक नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है।
- अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी स्टार्टअप इकाई, इसके निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि तक और जिसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे हरियाणा में इस नई नीति के तहत प्रमुख राजकोषीय और गैर-राजकोषीय लाभ लेने के लिये पात्र बन जाएंगे।
- इन लाभों में सब्सिडाइज्ड इन्क्यूबेशन स्पेस, हरियाणा सरकार की निविदाओं में भागीदारी के लिये उदार मानदंड, मेंटरशिप कार्यक्रमों में भागीदारी और अन्य स्टार्टअप विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं।
- इस नीति के कार्यान्वयन और अन्य संस्थागत गतिविधियों की निगरानी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग में एक स्टार्टअप हरियाणा प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।
- नीति के तहत इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिये गवर्नमेंट होस्ट इंस्टीट्यूट को 2 करोड़ रुपए तक तथा निजी होस्ट इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ रुपए तक का पूँजी अनुदान दिया जाएगा।
- इन्क्यूबेटर को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों में स्टार्टअप प्रतियोगिता उत्सव के आयोजन के लिये प्रति आयोजन 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
- राज्य सरकार ने स्टार्टअप हितधारकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिये नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 में कई नए प्रोत्साहन भी जोड़े हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं-
  - पंचकूला, हिसार और अन्य संभावित स्थानों पर आईटी स्टार्टअप वेयरहाऊस की स्थापना हेतु पूँजीगत व्यय के लिये 4 करोड़ रुपए तथा तीन साल के आवर्ती व्यय के लिये 1 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - इससे पहले, इनक्यूबेशन केंद्र में स्टार्टअप लाभ प्राप्त करने के लिये केवल एक वर्ष की अवधि हेतु पात्र थे। अब नई स्टार्टअप नीति में ऐसे स्टार्टअप सब्सिडाइज्ड दरों पर स्पेस, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के लिये तीन वर्ष हेतु लाभ ले सकते हैं।
  - राज्य सरकार हर छह महीने में हरियाणा के 22 जिलों में विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करेगी ताकि नई नीति के तहत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उनके विकास के अवसरों और क्षमता के बारे में इच्छुक इनोवेटर्स/उद्यमियों तथा स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच और जागरूकता पैदा की जा सके।

हरियाणा में पैक्स का होगा डिजिटलीकरण

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) का डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बताया कि डिजिटलीकरण के तहत 31 अगस्त, 2022 तक राज्य के 307 पैक्स पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। कंप्यूटरीकृत होने के बाद कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पैक्स के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।
- पैक्स को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, लेखांकन, लोन एवं एडवांस जैसी गतिविधियों को डिजिटलकृत करने के लिये ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, ताकि पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ कार्य सुगमता से हो सके।

नोट :

- संजीव कौशल ने बताया कि सीबीएस नेटवर्क के अंतर्गत तैयार विशेष मॉड्यूल के तहत पैक्स में पायलट आधार पर कंप्यूटरीकृत करने का कार्य किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। आगामी दिनों में पैक्स का विशेष मॉड्यूल के साथ एकीकरण कर दिया जाएगा।
- इसके अलावा, हरको बैंक और पैक्स को एक सिंगल सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। आगामी प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करते हुए नवंबर माह तक प्रदेश के सभी पैक्स पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे।

हरियाणा में गाँवों की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में गाँवों की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गाँव की तर्ज़ पर अब शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा के अंदर परिसंपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग इत्यादि की 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं।
- अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तथा प्राइवेट कॉलोनियों में जारी प्रॉपर्टी आईडी का एक मास्टर डाटा तैयार करें, ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके।
- इसके अलावा लाल डोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर समितियों के साथ साझा करें। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें।
- स्वामित्व योजना के तहत गाँवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रॉपर्टी कार्ड बनाने तथा वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा मुक्त करने का कार्य तेज़ी से किया जाएगा, ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके।
- गौरतलब है कि लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने ही शुरू की थी, जिसे बाद में देशभर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया। इस महत्त्वाकांक्षी योजना में गाँवों और शहरों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिये क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

नोट :